साप्ताहिक

डाक पंजीयनः म.प्र./भोपाल/4-479/2019-21

RNI-MPHIN/2015/72544

जागत गांव हमार

पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक

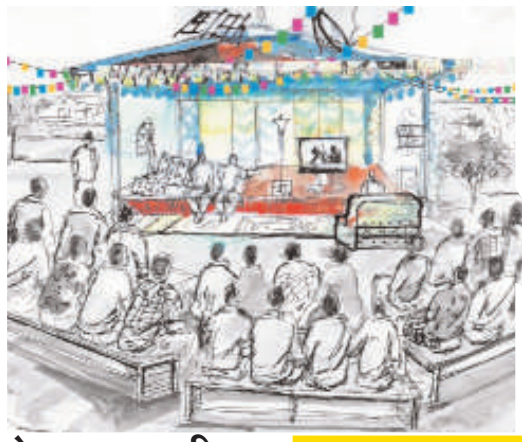

चौपाल से भोपाल तक

भोपाल, सोमवार 31 जनवरी-06 फरवरी 2022, वर्ष-7, अंक-44

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, रीवा, शिवपुरी से एक साथ प्रकाशित

पृष्ठ :-8, मूल्य :- 2 रुपए

अंगूठे के निशान से होगी किसान की पहचान, गेहूं खरीदी के लिए अब नहीं आएगा एसएमएस

मप्र में छन्ना लगाकर होगी गेहूं की खरीद

भोपाल। संवाददता

मध्य प्रदेश में इस बार समर्थन मूल्य पर गेहूं छन्ना लगाकर खरीदा जाएगा। जब किसान उपज लेकर उपार्जन केंद्र पर आएगा तो उसे छन्ने से छानकर लिया जाएगा ताकि गुणवत्तायुक्त अनाज की ही खरीद हो। इससे न तो समितियों को कोई परेशानी होगी और न ही किसानों को भुगतान में समस्या आएगी। उपज किसान की ही हो, यह सुनिश्चित करने के लिए उसकी पहचान अंगूठे का निशान लेकर की जाएगी। आधार के बायोमीट्रिक सत्यापन के बाद ही उपज बेची जा सकेगी। किसान का पंजीयन भी तभी होगा, जब उसका भू-अभिलेख के खाते एवं खसरे में दर्ज नाम का मिलान आधार कार्ड से हो। इसमें अंतर होने पर तहसील कार्यालय से सत्यापन कराया जाएगा और सही होने पर ही पंजीयन मान्य होगा। समर्थन मूल्य (एक हजार 975 रुपए प्रति क्विंटल) पर उपार्जन 25 मार्च से साढ़े तीन हजार से ज्यादा केंद्रों पर प्रारंभ होगा। सरकार का अनुमान है कि इस बार 140 लाख टन तक गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीद हो सकती है।

खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर होने वाली खरीद में गड़बड़ियों को रोकने के लिए व्यवस्था में परिवर्तन किया है। किसानों को पंजीयन कराने में असुविधा न हो, इसके लिए अब एमपी आनलाइन कियोस्क, कामन सर्विस सेंटर, लोक सेवा केंद्र और साइबर कैफे पर जाकर भी पंजीयन करा सकते हैं। इसके लिए उन्हें पचास रुपए शुल्क देना होगा। पंजीयन के समय किसान को बैंक खाता नंबर और आइएफएससी कोड नहीं देना होगा। यह जानकारी सरकार आधार नंबर से लेगी।

ताकि भुगतान में न हो समस्या

प्रदेश के साभी कलेक्टरों को विभाग ने निर्देश दिए हैं कि वे किसानों को जागरुक करें कि आधार नंबर के साथ मोबाइल नंबर और बैंक खाते को अपडेट करें ताकि भुगतान में कोई समस्या न आए। गुणवत्तायुक्त उपज की ही खरीद हो, इसके लिए उपार्जन केंद्रों पर छन्ना लगाया जाएगा। किसान उपज को छानकर देगा। इससे फायदा यह होगा कि उपज लेने के बाद उसे अमानक नहीं ठहराया जा सकेगा।

किसानों की कटेगी राशि

पिछले साल एक लाख टन गेहूं को बाद में अमानक करार दिया गया था। इसका नुकसान समितियों को उठाना पड़ता है, क्योंकि उपार्जन से संबंधित सभी जिम्मेदारी उन्हीं की होती है। छन्ना लगाने का काम निजी संस्था को दिया जाएगा और प्रति क्विंटल जो राशि तय होगी, उसका भुगतान किसान को करना होगा। राशि का निर्धारण शासन स्तर से बाद में होगा।

किसानों को बताना होगी तारीख

पंजीयन के समय भूमि का क्षेत्र, फसल की किस्म की जानकारी देनी होगी। इससे सरकार को कार्ययोजना बनाने में मदद मिलेगी। किराए पर भूमि लेकर खेती करने वाले, बटाईदार और वन पट्टाधारी को पंजीयन कराने के लिए केंद्र ही जाना होगा। यह भी बताना होगा कि वे कितनी उपज बेचेंगे और उसे भंडारित करके कहां रखा है। उपज बेचने के लिए एमएसएम नहीं भेजे जाएंगे। इसके स्थान पर उन्हें केंद्र, उपज बेचने के लिए लाने की तारीख और स्लाट का चयन करना होगा।

सरकार ने जारी की उपार्जन नीति | प्रदेश में किसानों की फसल खरीदी में होने वाले फर्जीवाड़ा रोकने सहित गेहूं खरीदी व्यवस्था को सहज और सुगम बनाने राज्य सरकार ने उपार्जन नीति में बड़ा फेरबदल किया है। रबी विपणन वर्ष 2022-23 की जारी नीति के अनुसार, इस बार किसानों को गेहूं खरीदी के लिए किसी भी तरीके से एसएमएस नहीं भेजा जाएगा। न ही उनकी खरीदी गई फसल के भुगतान के लिए बैंक खाता नंबर व आईएफएससी नंबर मांगा जाएगा।

समितियों में होगा पंजीयन

किसानों का पंजीयन सिर्फ सहकारी समितियों में होगा। इनका शत-प्रतिशत सत्यापन राजस्व विभाग करेगा। फसल बेचने से पहले होगा आधार वैरीफिकेशन पंजीयन कराने व फसल बेचने के लिए आधार नंबर का सत्यापन अनिवार्य होगा। यह आधार नंबर से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी से या बायोमैट्रिक डिवाइस से किया जा सकेगा।

बदल गई उपार्जन प्रक्रिया

अब तक किसानों को खरीदी के एसएमएस आते थे। एसएमएस में मिली तिथि के अनुसार ही किसान फसल बेच सकता था। इस बार एसएमएस की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। फसल बेचने के लिए अब किसान तय पोर्टल से नजदीक के उपार्जन केंद्र, तिथि टाइम सस्लॉट का चयन खुद कर सकेंगे। इसका चयन नियत तिथि के पहले करना होगा। सामान्य तौर पर उपार्जन प्रारंभ होने की तिथि के एक सप्ताह पहले तक उपार्जन केंद्र, तिथि व टाइम स्लॉट का चयन किया जा सकेगा।

पंजीयन कराने और उपज बेचने के लिए आधार नंबर से सत्यापन कराया जाएगा। आधार नंबर से जो मोबाइल नंबर लिंक होगा, ओटीपी उसी पर आएगा। किसान का पंजीयन तभी होगा जब भू-अभिलेख में दर्ज खाते एवं खसरे में दर्ज नाम का मिलान आधार कार्ड में दर्ज नाम से होगा। यदि इसमें अंतर पाया जाता है तो फिर तहसील कार्यालय से सत्यापन कराया जाएगा।
फैज अहमद किदवई, प्रमुख सचिव, कृषि विभाग

कलेक्टर सुस्तः ओलावृष्टि की 25 जिलों से आई रिपोर्ट

आहत किसानों को नहीं मिली राहत

फसल नुकसान का रकबा डेढ़ लाख हेक्टेयर के पार

प्रारंभिक आकलनः500 करोड़ देनी होगी आर्थिक सहायता

सीएम ने कहा थाः सात दिन में होगा सर्वे, तीन दिन बाद राहत बांटी जाए

भोपाल। संवाददाता

प्रदेश के कई जिलों में हुई ओलावृष्टि के 15 दिन बाद भी किसानों को राहत राशि बांटने का काम शुरू नहीं हो पाया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर नौ जनवरी को सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए थे कि किसानों की फसल का जो नुकसान हुआ है, उसका तत्काल सर्वे कर राहत राशि दी जाए। इसके लिए एक सप्ताह का समय तय किया गया था। इसके बावजूद 15 दिन बीतने के बाद भी किसानों को न तो राहत मिली है और न ही सर्वे का कार्य पूरा किया गया है। अब तक 25 जिलों में डेढ़ लाख हेक्टेयर भूमि पर फसल के नुकसान का आकलन किया गया है। मध्य प्रदेश में ओलावृष्टि से रबी फसलों को पहुंचे नुकसान के आकलन का सर्वे नौ जनवरी से कराया जा रहा है। अभी 25 जिलों से प्रारंभिक रिपोर्ट आई है। इसमें फसल नुकसान का रकबा डेढ़ लाख हेक्टेयर को पार कर गया है। 70 तहसीलों के एक हजार 157 गांवों के एक लाख 67 हजार 201 किसानों की फसल को क्षति हुई है।

सर्वे का काम अभी चल रहा है, जो जल्द ही पूरा हो जाएगा। कोरोना के कारण सर्वे में कुछ विलंब हुआ है। फिर भी हमारी कोशिश है कि राहत बांटने का काम जल्द प्रारंभ कर दें।
मनीष रस्तोगी, प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग

दावे-आपत्ति के कारण हो रहा विलंब

प्रदेश के किसानों को ओलावृष्टि से हुए नुकसान में राहत पाने के लिए अभी कम से कम एक सप्ताह का समय और लगेगा। इसकी वजह सर्वे में विलंब तो है ही, साथ में पंचायत स्तर पर किसानों को हुए नुकसान पर दावे-आपत्ति में विलंब भी एक कारण है। यही वजह है कि राज्य सरकार ने कलेक्टरों को सर्वे में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने यह भी तय किया है कि जिन जिलों में सर्वे का कार्य पूरा हो जाए, वहां राहत बांटने का काम प्रारंभ कर दिया जाए।

सभी जिलों में हो रहा सर्वे

किसानों को राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रविधान अनुसार आर्थिक सहायता देने के लिए लगभग 500 करोड़ रुपए से अधिक की जरूरत पड़ेगी। यह राशि सभी जिलों को आपदा राहत फंड से ग्लोबल हेड में उपलब्ध कराई जाएगी। छह से 10 जनवरी के बीच प्रदेश में ओलावृष्टि से रबी फसलें प्रभावित हुई हैं। फसल क्षति का आकलन करने के लिए सभी जिलों में सर्वे कराया जा रहा है।

कृषि मंत्री ने मधु को दूसरे किसानों के लिए प्रेरणास्रोत

हरदा में उद्यानिकी फसलों ने किसान को बनाया करोड़पति

-मंत्री ने जाना उत्पादन पर आने वाली लागत और मुनाफा

-टमाटर, मूंगफली, मिर्च, शिमला मिर्च, अदरक उगा रहे

भोपाल। मध्य प्रदेश के हरदा जिले में एक किसान परिवार के लिए परंपरागत खेती के स्थान पर उद्यानिकी का अपनाना बदलाव का कारण बन गया है। अब यह परिवार करोड़पति बनने के साथ अन्य किसानों के लिए आदर्श भी बन गया है। दरअसल, सिरकंबा ग्राम में है उन्नत किसान मधु धाकड़ का संयुक्त परिवार, जो संयुक्त रूप से खेती के काम में लगा है। बीते कुछ वर्षों से इस किसान परिवार ने खेती के तरीके को बदला, यह बदलाव उनके लिए एक क्रांतिकारी परिवर्तन साबित हुआ है। यह किसान परिवार भी अन्य किसानों की तरह गेहूं, चना, सोयाबीन जैसी परंपरागत फसलों की खेती करता रहा है, मगर बीते सालों में इस परिवार ने परंपरागत खेती की जगह उद्यानिकी को चुना और अपनी डेढ़ सौ एकड़ जमीन पर टमाटर, मूंगफली, मिर्च, शिमला मिर्च और अदरक उगा कर समृद्धि का नया मार्ग खोल लिया। राज्य के कृषि मंत्री कमल पटेल ने इस परिवार से मुलाकात की और खेती के तरीके में बदलाव लाने की वजह भी जानी। मंत्री को मधु धाकड़ से बताया कि कुल 150 एकड़ क्षेत्र में टमाटर, शिमला मिर्च, अदरक के लिए वर्गीकृत किया है और उसी के अनुसार खेती करते हैं। प्रत्येक फसल के उत्पादन पर आने वाली लागत और मुनाफे की जानकारी ली।

सीहोर में अमरूद, मुरैना में सरसों और अन्य तिलहन, ग्वालियर में आलू पर आधारित होंगे इन्क्यूबेशन सेंटर

किसान खुद स्थापित करें कृषि उत्पादों की प्रोसेसिंग इकाइयां

सीएम शिवराज बोले- उत्पादन गुणवत्ता सुधार, मार्केटिंग एवं ब्रांडिंग प्रशिक्षण के लिए किसानों की कार्यशालाएं कराएं

- » किसानों की आय बढ़ाने कृषि का विविधीकरण आवश्यक
- » आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूर्ण करने मध्यप्रदेश दे रहा सहयोग
- » फूड प्रोसेसिंग इकाइयां ग्रामीणों के पलायन को कम करने में सहायक
- » मुख्यमंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री ने किया ग्वालियर, मुरैना और सीहोर के इन्क्यूबेशन सेंटर्स का किया श्रीगणेश

भोपाल। संवाददाता

मध्यप्रदेश संतरा, धनिया, लहसुन उत्पादन में देश में पहले नंबर पर है। अदरक, मिर्ची, अमरुद, मटर और प्याज के उत्पादन में प्रदेश पूरे देश में दूसरे नंबर पर है। अगर किसान अपने इस उत्पादन की छोटी-छोटी फूड प्रोसेसिंग इकाई खोल लें, तो जनता को शुद्ध सामग्री, युवाओं को रोजगार के अवसर और किसानों को उनके उत्पाद के ठीक दाम मिल सकेंगे। प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना बनाकर ऐतिहासिक कदम उठाया है। इस योजना में ग्वालियर, मुरैना और सीहोर के इनक्यूबेशन सेंटर निश्चित तौर पर मील का पत्थर साबित होंगे। यह बात सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के अंतर्गत कृषि महाविद्यालय ग्वालियर, कृषि विज्ञान केंद्र, मुरैना और कृषि महाविद्यालय, सीहोर में इन्क्यूबेशन केन्द्रों की स्थापना के लिए राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विवि, ग्वालियर में आयोजित भूमि-पूजन एवं शिलान्यास समारोह के दौरान कही। कार्यक्रम का अयोजन वर्चुअली किया गया था। जिसमें केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर, प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल, उद्यानिकी राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाह भी शामिल हुए थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि खाद्य प्र-संस्करण की प्रक्रिया पर प्रदेश में कार्यशालाएं आयोजित करने की जरूरी है। किसानों को अपने उत्पाद की गुणवत्ता सुधार, पैकेजिंग, मार्केटिंग, ब्रांडिंग के संबंध में जानकारी देने और इनकी प्रक्रियाओं से अवगत कराने के लिए कार्यशालाएं आयोजित की जाएं। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना में किसान को 10 लाख तक की सब्सिडी दी जाएगी। अनुदान का 40 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को विस्तार देने के लिए राज्य सरकार बड़ी यूनिट लगाने पर ढाई करोड़ तक की सब्सिडी देगी।

किसानों की आय बढ़ाने कृषि का विविधीकरण आवश्यक

पिछले 15 साल में प्रदेश ने कृषि के क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि की है। अनेक योजनाएं बनाकर हमने तय किया कि प्रदेश को कृषि के क्षेत्र में आगे लाएंगे। इसी का परिणाम है कि प्रदेश को अनेक बार कृषि कर्मण अवार्ड प्राप्त हुआ। मध्यप्रदेश ने कृषि उत्पादन में रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। प्रदेश में 43 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान खरीदकर रिकॉर्ड स्थापित किया गया है। आज मप्र में पंजाब से भी अधिक गेहूं पैदा होता है। मप्र कृषि के क्षेत्र में नित नए कीर्तिमान स्थापित करते हुए प्रधानमंत्री के आत्म-निर्भर भारत के संकल्प को पूर्ण करने में सतत् सहयोग प्रदान कर रहा है। कृषि देश की अर्थ-व्यवस्था की रीढ़ है। राज्य सरकार फसलों के उत्पादन के साथ उद्यानिकी को प्रोत्साहित कर प्रधानमंत्री के किसानों की आय दोगुनी करने के संकल्प को पूरा करने की दिशा में सक्रिय है। किसान की आय बढ़ाने के लिए कृषि के विविधीकरण की आवश्यकता है। फल, फूल, सब्जी, औषधियों की खेती और कृषि वानिकी को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। प्रदेश में उद्यानिकी का क्षेत्र 15 लाख हेक्टेयर से अधिक हो गया है। प्रदेश में फल, सब्जियां, मसाले आदि की बड़े पैमाने पर खेती हो रही है। इन उत्पादों की प्रोसेसिंग की व्यवस्था होने से निश्चित रूप से किसानों की आय बढ़ेगी। देश में असंगठित खाद्य प्र-संस्करण क्षेत्र में लगभग 25 लाख इकाइयां कार्य कर रही हैं। इनमें से लगभग 66 प्रतिशत यूनिट ग्रामीण क्षेत्रों में हैं और लगभग 80 प्रतिशत उद्यम परिवार आधारित हैं। यह उद्यम, ग्रामीण पारिवारिक आजीविका को बढ़ाने और ग्रामीणों के शहरी क्षेत्रों में पलायन को कम करने में सहायक हैं। इसलिए ग्राम स्तर पर खाद्य प्र-संस्करण के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी और उपकरणों की उपलब्धता, प्रशिक्षण, संस्थागत ऋण की उपलब्धता, उत्पादों के गुणवत्ता नियंत्रण के संबंध में जानकारी तथा सामग्री की पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग के संबंध में आवश्यक प्रशिक्षण और वेल्यू एडिशन पर सही मार्गदर्शन उपलब्ध कराकर युवाओं को सशक्त करने की जरूरी है।

ग्वालियर में होगी प्याज प्र-संस्करण लाइन

केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि कोविड के समय जब अन्य आर्थिक गतिविधियां बंद थी, उस समय कृषि ने ही अर्थ-व्यवस्था को आधार प्रदान किया। भारत सरकार और मध्यप्रदेश शासन द्वारा संचालित योजनाओं से निश्चित ही गरीब और किसानों के जीवन में बदलाव आएगा। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि इन्क्यूबेशन सेंटर्स की स्थापना से किसानों को अपने उत्पादों की प्रोसेसिंग का अवसर मिलेगा। इससे किसानों की आय में निश्चित ही वृद्धि होगी। उद्यानिकी राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाह ने कहा कि प्रदेश को प्रोसेसिंग हब के रूप में विकसित करने के लिए निरंतर कार्य जारी है। सीहोर, मुरैना और ग्वालियर में तीन इन्क्यूवेशन सेंटर्स की स्थापना के लिए भारत सरकार द्वारा 9 करोड़ 87 लाख 85 हजार स्वीकृत किए हैं। सीहोर में अमरूद, फलों तथा सब्जियों के प्र-संस्करण के लिए इन्क्यूबेशन सेंटर की स्थापना की जा रही है। सेंटर में खाद्य प्र-संस्करण प्रयोगशाला सहित जूस, पल्प, जैम, जैली, वेजिटेबल डिहाइड्रेशन लाइन एवं प्याज प्र-संस्करण लाइन की स्थापना होगी। मुरैना में सरसों एवं अन्य तिलहनों, ज्वार, बाजरा, रागी और बेकरी उत्पादों के प्र-संस्करण के लिए कॉमन इन्क्यूबेशन फेसिलिटी उपलब्ध कराई जाएगी। ग्वालियर में आलू तथा आलू प्र-संस्करण लाइन एवं मिलेट आधारित कुकीज लाइन की स्थापना की जा रही है।

जैविक खेती करने वाले किसानों के बनेंगे समूह

ग्वालियर में फूलों की आधुनिक नर्सरी बनेगी

मंत्री भारत सिंह कुशवाह बोले-किसान खरीदने के लिए स्वतंत्र रहेगा

ग्वालियर। संवाददाता

शहर में आधुनिक नर्सरी के साथ अब जैविक खेती करने वाले किसानों का समूह बनाया जाएगा। जिससे खेती की पैदावार का उचित दाम किसानों को मिल सके और योजनाओं का लाभ भी शासन से मिले। समूह के तौर पर जब किसान

पैदावार करेंगे तो वह अपनी पूरी फसल को शहर से बार विदेश तक पहुंचा सकेंगे। जिससे उनकी फसल का उन्हें उचित दाम मिलेगा। इसी सोच के साथ अब सरकार काम कर रही है। जिससे किसानों की आय को बढ़ाया जा सके और लोगों को जैविक खेती की ओर मोड़ा जा सके। ग्वालियर में फूलों की आधुनिक नर्सरी की स्थापना के लिए इस क्षेत्र में अनुभव रखने वाली विशेषज्ञ फर्म का चयन किया जाए और उससे डीपीआर बनवाई जाएगी। फ्लोरीकल्चर गार्डन अपने प्रकार का प्रदेश का पहला आधुनिक नर्सरी होगी। पीएमएफएमई योजना फार्म लाइजेशन आरके माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस में आनलाइन आवेदनों की स्थिति में सुधार हुआ है। बैंकों में अब तक कुल आवेदन 1327 पहुंचे। जिसमें से 175 में स्वीकृति दी गई है और 522 प्रकरण विचाराधीन हैं।

किसानों के खाते में सीधे अनुदान राशि डालें

इधर, उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाह ने कहा है कि शेडनेट हाउस और पॉली-हाउस बनाने वाले किसानों के खातों में अनुदान राशि डायरेक्ट ट्रांसफर की जाए। किसान निर्धारित स्पेशिफिकेशन की सामग्री को वेंडर से खरीदने के लिए स्वतंत्र रहेगा। राज्य मंत्री मंत्रालय में विभागीय समीक्षा कर रहे थे। एसीएस उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण जेएन कंसोटिया, उद्यानिकी आयुक्त ई रमेश कुमार और एमडी एमपी एग्रो राजीव कुमार जैन बैठक में मौजूद थे। राज्य मंत्री ने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष में संरक्षित खेती, शेडनेट हाउस और पॉली-हाउस योजना में 98 हजार वर्ग मीटर में 31 किसानों द्वारा शेडनेट हाउस और पॉली-हाउस बनाने का प्रस्ताव दिया गया है।

किसान खरीदेंगे सामान

राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाह ने विभागीय अधिकारियों को बैंकों से समन्वय कर सभी प्रकरणों में स्वीकृतियां दिलाने के निर्देश दिए। शेडनेट व पाली हाउस बनाने वाले किसानों के खाते में अनुदान राशि पहुंचाई जाएगी। मंत्री ने कहा कि किसान निर्धारित स्पेसिफिकेशन की सामग्री को वेंडर से खरीदने के लिए स्वतंत्र रहेगा। किसान मनचाहे वेंडर से सामान खरीदे, इसलिए राशि उसके खाते में ही मिलना चाहिए। जिससे किसान अपनी जरुरत के हिसाब से सामान खरीद सकेगा।

पाल हाउस बनाने का प्रस्ताव

राज्य मंत्री ने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष में संरक्षित खेती, शेडनेट हाउस और पाली-हाउस योजना में 98 हजार वर्ग मीटर में 31 किसानों द्वारा शेडनेट हाउस और पाली-हाउस बनाने का प्रस्ताव दिया है। राज्यमंत्री ने कहा कि जैविक उद्यानिकी खेती करने वाले किसानों की जिलेवार सूची बनाई जाए, जिससे उनका एक समूह बनाया जा सके। किसानों को जैविक पद्धति से उद्यानिकी फसल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इसके साथ ही हर जिले में एक उद्यानिकी फसल का उत्पादन हो, जिससे तैयार प्रोडक्ट का निर्यात अन्य राज्यों व विदेशों में किया जा सके।

सभी देशवसियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं...
श्रीमति असरफी पति मेघसिंह जाटव
सरपंच
श्री भागीरथ कोली
सचिव
श्री देवेन्द्र राजपूत
रोज सहायक
ग्राम पंचायत ग्वालिया जनपद पंचायत नरवर जिला शिवपुरी मध्य-प्रदेश

सभी देशवसियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं...
श्रीमति लक्ष्मी बाई बघेल
सरपंच
श्री उत्तम सिंह लोधी
सचिव
श्रीमती नीतू रावत
रोज सहायक
ग्राम पंचायत खड़ीचा जनपद पंचायत नरवर जिला शिवपुरी मध्य-प्रदेश

सभी देशवसियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं...
श्रीमती प्रेमलता पति रामेश्वर सोनी
सरपंच
श्री संतोष शर्मा
सचिव
हरप्रसाद जाटव
रोजगार सहायक
ग्राम पंचायत फतेहपुर जनपद पंचायत नरवर जिला शिवपुरी मध्य-प्रदेश

सभी देशवसियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं...
श्रीमती गीता रावत पति श्री अशोक रावत
सरपंच
श्री गोविन्द सिंह कुशवाहा
सचिव
ग्राम पंचायत दिहायला जनपद पंचायत नरवर जिला शिवपुरी मध्य-प्रदेश

सभी देशवसियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं...
श्रीमती फूलवती कुशवाहा
सरपंच
श्री देशराज कुशवाहा
सचिव
ग्राम पंचायत चकरामपुर जनपद पंचायत नरवर जिला शिवपुरी मध्य-प्रदेश

सभी देशवसियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं...
श्री महावीर राय
सरपंच
श्री कृष्णपाल सिंह परमार
सचिव
कमल किशोर जाटव
रोजगार सहायक
ग्राम पंचायत वीरा जनपद पंचायत पिछोर जिला शिवपुरी मध्य-प्रदेश

सभी देशवसियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं...
श्रीमती विमला पाल पति श्री उदयराम पाल
सरपंच
श्री गोपाल लोधी
सचिव
ग्राम पंचायत जुझाई जनपद पंचायत करैरा जिला शिवपुरी मध्य-प्रदेश

सभी देशवसियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं...
सरपंच श्रीमती मीरा गुर्जर पति श्री राजेन्द्र सिंह गुर्जर
सरपंच
श्री मुकेश रावत
सचिव
श्री बीरवल कुशवाहा
रोजगार सहायक
ग्राम पंचायत शिलानगर जनपद पंचायत करैरा जिला शिवपुरी मध्य-प्रदेश

सभी देशवसियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं...
श्री बादाम सहरिया
सरपंच
श्री धर्मेंद्र रावत
सचिव
श्री रविन्द्र रावत
रोजगार सहायक
ग्राम पंचायत कैरुआ जनपद पंचायत नरवर जिला शिवपुरी मध्य-प्रदेश

सभी देशवसियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं...
श्री ज्ञानेन्द्र बुंदेला
सरपंच
राकेश पाल
सचिव
ग्राम पंचायत सलैया डामरौन जनपद पंचायत करैरा जिला शिवपुरी मध्य-प्रदेश

सभी देशवसियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं...
श्री मति हरकुंअर पाल
सरपंच
प्रीतम पाल
सचिव
मनीराम जाटव
रोजगार सहायक
ग्राम पंचायत डुमघना जनपद पंचायत करैरा जिला शिवपुरी मध्य-प्रदेश

सभी देशवसियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं...
श्री राजू जाटव
सरपंच
राजेन्द्र सिंह कुशवाहा
सचिव
श्री कैलाश गौतम
रोजगार सहायक
ग्राम पंचायत रामनगर(गधाई) जनपद पंचायत नरवर जिला शिवपुरी मध्य-प्रदेश

सभी देशवसियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं...
सरपंच श्री मति सीमा लोधी पति श्री अवधेश लोधी
सरपंच
सोन सिंह जाटव
सचिव
सुरेन्द्र तिवारी
रोजगार सहायक
ग्राम पंचायत बनोटा जनपद पंचायत खनियाधाना जिला शिवपुरी मध्य-प्रदेश

सभी देशवसियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं...
सरपंच हरविलास जाटव
सरपंच
श्री राजेन्द्र सिंह यादव
सचिव
श्रीमती प्रियंका गुप्ता
रोजगार सहायक
ग्राम पंचायत अमरपुर देवरा जनपद पंचायत खनियाधाना जिला शिवपुरी मध्य-प्रदेश

सभी देशवसियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं...
श्रीमति सरोज जाटव पति श्री मोहन जाटव
सरपंच
श्री जितेन्द्र सोहरे
सचिव
श्री चतुर सिंह जाटव
रोजगार सहायक
ग्राम पंचायत ताल भेव जनपद पंचायत नरवर जिला शिवपुरी मध्य-प्रदेश

ग्रामीण क्षेत्रों में घर-घर तक पहुंच रहा नल से जल

अशोक मनवानी
मध्यप्रदेश जनसंपर्क के अधिकारी

प्रदेश की ग्रामीण आबादी के वे सभी ग्राम हर घर-जल ग्राम घोषित किए जा रहे हैं, जहां ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाई जा चुकी है। ऐसे 4045 ग्राम हैं, जिनमें यह शुरुआत हो रही है। अब इन ग्रामों में अब नल के माध्यम से पेयजल मिल रहा है। इनमें 46 लाख से अधिक ग्रामीण परिवार यह सुविधा पाकर हर्षित हैं। ग्रामीण माताएं और बहनें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को दुआएं दे रही हैं। उनके जीवन की एक बड़ी कठिनाई तो दूर हुई, साथ ही मानव श्रम और समय की भी बचत संभव हुई है। ग्रामीण माताएं और बहनें जिन पर घर में पीने का पानी लेकर आने का दारोमदार होता है, उनके जीवन की कठिनाइयां दूर करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की पहल जल जीवन मिशन से रंग ला रही है।

मध्यप्रदेश में 4 हजार से अधिक ग्रामों में नल से पेयजल प्रदाय की व्यवस्था फलीभूत हुई है। इस कार्य को मजबूत संकल्प और संवेदनशील मन के साथ ही किया जा सकता था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल कर बीते दो वर्ष में अनेक बार जल जीवन मिशन के कार्यों की जानकारी ली और नियमित बैठकें कर कार्य प्रगति की समीक्षा की। सामने आई कमियों को दूर करने की हिदायत दी और अच्छे परिणाम लाने के लिए अमले को प्रोत्साहित भी किया। इसके फलस्वरुप मध्यप्रदेश मिशन के कार्यों में देश में अग्रणी है। मध्यप्रदेश जल जीवन मिशन के कार्यों में यूं ही अग्रणी नहीं है। इसके लिए यहाँ सतत समीक्षा का कार्य मुख्यमंत्री स्तर पर हुआ है। मुख्यमंत्री प्रदेश की शहरी और ग्रामीण आबादी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के कार्यों को समय-सीमा में पूर्ण करने पर जोर देते रहे हैं। उनका कहना है कि आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के लिए निर्मित रोडमैप में निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार प्रदेश में समस्त नलजल योजनाओं के कार्य सम्पन्न होना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने योजनाओं के बेहतर संधारण के लिए ग्राम इंजीनियर पदस्थ करने को कहा है। उन्होंने वृहद परियोजना के कार्यों में समय पर कार्यों की पूर्णता के लिए संबंधित एजेंसी और अधिकारी-कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि विलंब से होने वाले कार्यों पर जिम्मेदारी तय कर दोषियों के विरुद्ध सख्त कदम उठाए जाएं। नलजल योजनाओं का कार्य पूर्ण होने पर ग्रामों में विशेष ग्राम सभा आयोजित कर ग्राम को हर घर जल ग्राम श्रेणी का ग्राम घोषित किया जाए। योजना के निर्माण कार्य पूरे होने पर संबंधित पंचायत को योजना हस्तांतरित की जाए। ग्राम जल और स्वच्छता समिति के पदाधिकारी ग्रामवासियों से जन-संवाद भी करेंगे। प्रधानमंत्री को ऐसी महत्वाकांक्षी और उपयोगी योजना लागू करने के लिए ग्रामवासियों द्वारा आभार-पत्र भी भेजे जाएंगे। मुख्यमंत्री का मानना है कि ग्राम स्तर पर ऐसे ग्रामीण इंजीनियर को तैनात किया जाए जो विद्युत कनेक्शन, पेयजल प्रदाय व्यवस्था, सिंचाई पम्पों से संबंधित प्रबंध, आवास निर्माण के तकनीकी पहलुओं आदि की जानकारी रखता हो। पम्प और वाल्व ऑपरेटर का प्रशिक्षण कुछ ही दिनों में दिया जा सकता है। बेरोजगार युवाओं को इन कार्यों के लिए तीन से छह माह के छोटे प्रशिक्षण कोर्स का लाभ दिलवाकर ग्रामों में पेयजल प्रदाय योजना और अन्य योजनाओं में मेन्टेनेंस का दायित्व सौंपा जाए। मध्यप्रदेश में इस क्षेत्र में एक मॉडल तैयार कर उसके क्रियान्वयन की पहल की जाए। इसके लिए ग्रामीण विकास विभाग नोडल विभाग की भूमिका का निर्वहन करे। बड़े ग्रामों में एक से अधिक युवक भी यह जिम्मेदारी वहन कर सकते हैं।

मध्यप्रदेश में मार्च 2021 तक ग्रामीण क्षेत्रों में पाइपलाइन द्वारा जल प्रदाय की उपलब्धता 30.55 प्रतिशत हो गई, जो वर्तमान में 37.10 प्रतिशत है। विभिन्न नलजल योजनाओं पर 42 हजार 643 करोड़ रुपए की राशि खर्च हो रही है। गत वित्त वर्ष में 26 लाख घरों तक पेयजल कनेक्शन के लक्ष्य के विरुद्ध करीब 20 लाख घरों में नल कनेक्शन दिए गए, जो लक्ष्य का तीन चौथाई है। वर्ष 2024 तक मध्यप्रदेश के सभी लगभग 122 लाख ग्रामीण परिवारों तक पेयजल उपलब्धता के लक्ष्य के मुकाबले गत दिसम्बर तक 45 लाख 10 हजार परिवारों तक पेयजल उपलब्ध करवाया जा चुका था। अभी यह संख्या 46 लाख से अधिक हो गई है। अगले तीन माह में 52 लाख 62 हजार परिवारों तक पेयजल उपलब्ध होगा। नल और बिजली से जुड़े मरम्मत कार्यों के लिए 50 हजार मैकेनिक प्रशिक्षित करने की योजना है। इस लक्ष्य पूर्ति के लिए मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास और रोजगार निर्माण बोर्ड के माध्यम से आईटीआई और अन्य संस्थाएँ प्रशिक्षण प्रारंभ कर चुकी हैं। जल जीवन मिशन में ग्राम और एफएचटीसी (फंक्शनल हाउस होल्ड टेप कनेक्शन) कार्य-योजना में 25 हजार 399 ग्रामों की समूह नल जल योजनाओं में से 9 हजार 351 कार्य प्रगति पर हैं। कुल 26 हजार 186 ग्रामों की एकल ग्राम नल जल योजना में 8 हजार 176 कार्य प्रगति पर हैं। यह व्यवस्था भी की गई है कि योजना के क्रियान्वयन के लिए सड़क खुदाई की अनुमति के लिए कांट्रेक्टर जल निगम के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करेगा। यह अनुमति अलाइनमेंट परीक्षण के बाद प्रदान की जाएगी और उसके बाद ही कांट्रेक्टर रोड कटर का उपयोग करेगा। पाइप लाइन डालने के बाद कांट्रेक्टर द्वारा सड़क की आवश्यक मरम्मत करवाई जाएगी। सड़क को पूर्वास्था में लाने के लिए योजना की डीपीआर में प्रावधानित राशि का भुगतान किया जाएगा। भारत सरकार की जल जीवन मिशन योजना में वित्त वर्ष 2021-22 में केंद्रांश- राज्यांश की राशि के व्यय में मध्यप्रदेश 2,790 करोड़ की राशि का उपयोग कर प्रथम स्थान पर है। हर घर जल उपलब्ध करवाने में मप्र तीसरे स्थान पर है, जहां हाल ही में 4,044 अतिरिक्त ग्राम में यह सुविधा दिलवाई जा चुकी है। पिछले डेढ़ साल में काफी गति से कार्य हुआ है। प्रदेश में मई 2020 से वर्तमान तक 27 लाख 65 हजार परिवारों को नल से जल उपलब्ध कराया गया था। इस अवधि में प्रदेश का नल से जल आपूर्ति का प्रतिशत 14.5 से बढ़कर 37.10 प्रतिशत तक पहुंच गया है। मप्र ऐसा एकमात्र राज्य है जहां समस्त जिला स्तरीय पेयजल परीक्षण प्रयोगशालाएं एनएबीएल प्रमाणित हैं। मिशन से तेजी से क्रियान्वय के लिए प्रदेश के बजट में वर्ष 2020-21 में इस कार्य के लिए तीन गुना अधिक राशि दी गई। वर्तमान वित्त वर्ष में देश में मध्यप्रदेश को सबसे पहले प्रथम किश्त की द्वितीय ट्रांच राशि 1247 करोड़ प्राप्त हुई है। यह मध्यप्रदेश के लिए एक विशेष उपलब्धि है।

राष्ट्र पर राहुल गांधी की लचर दलील

अनंत विजय

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने संसद में कुछ ऐसी बातें कहीं जिस पर, उनको लगता है कि चर्चा की जानी चाहिए। पहली बात तो उन्होंने ये कही कि भारत राष्ट्र नहीं है और ये राज्यों का संघ है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों को भारतीय संविधान पढ़ने की भी सलाह दी और कहा कि संविधान में लिखा है कि भारत राज्यों का संघ है और वो राष्ट्र नहीं है। संविधान के अनुच्छेद एक में ये अवश्य लिखा है कि भारत राज्यों का संघ होगा, लेकिन पूरे संविधान में ये कहीं नहीं लिखा है कि भारत एक राष्ट्र नहीं है। दरअसल राहुल गांधी ने संविधान का अनुच्छेद एक तो पढ़ लिया, लेकिन वो संविधान की प्रस्तावना पढ़ना भूल गए, प्रतीत होता है।

संविधान की मूल प्रस्तावना और इमरजेंसी के समय हुए संशोधन के बाद की प्रस्तावना में भारत के लिए राष्ट्र शब्द का उल्लेख है। प्रस्तवाना में लिखा है कि ...उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए...। ये तो स्पष्ट कि संविधान भारत को एक राष्ट्र के तौर पर देखता है। अगर संविधान की प्रस्तावना और संविधान सभा की बहस को देखें तो ये अधिक स्पष्ट होता है। संविधान सभा की बहस में राज्यों के यूनियन आफ स्टेट्स और फेडरल शब्द के उपयोग को लेकर लंबी बहस हुई थी।

उस बहस में बाबा साहब अंबेडकर, प्रो के टी शाह, एच वी कामथ आदि ने हिस्सा लिया था। भारत औप भारत वर्ष नाम पर भी लंबी चर्चा हुई थी। तमाम दलीलों के बाद भारत को राज्यों के संघ के तौर पर स्वीकृत किया गया था। फेडरल स्टेट की मांग को खारिज कर दिया था। दरअसल, राजनीतिक भाषणों में जब अकादमिक पुट दिया जाता है तो इस तरह की त्रुटियां हो जाती हैं, क्योंकि राजनीतिक भाषणों में समग्रता में अपनी बात कहने का अवसर नहीं होता है जबकि अकादमिक बहसों या लेखन में अपनी बात समग्रता में कही जा सकती है। राहुल गांधी की चिंता राज्यों के अधिकारों को लेकर है। सविंधान के अलग अलग अनुच्छेद में राज्यों के अधिकारों की चिंता की गई है। ये बात संविधान सभा की बहस में बाबा साहेब अंबेडकर ने भी कई बार दोहराई है। जब राहुल गांधी भारत के राष्ट्र होने की अवधारणा का निषेध करते हैं तो वो जाने अनजाने कम्युनिस्टों के सोच को आगे बढ़ाते प्रतीत होते हैं। देश की स्वाधीनता के बाद कम्युनिस्टों ने भी राष्ट्र की अवधारणा को, लोकतंत्र की अवधारणा को, लोक कल्याणकारी राज्य का निषेध किया था। कम्युनिस्ट हमेशा से अंतराष्ट्रीयता को मानते रहे। यह अनायस नहीं है कि उनकी पार्टी का नाम भारत की कम्युनिस्ट पार्टी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नहीं। कम्युनिस्ट विचारधारा लोक कल्याणकारी सबल राष्ट्र की पक्षधर नहीं रही है। कम्युनिस्ट पार्टियों में ये बहस चलती रही है कि सरकार की नीतियों को गरीबों तक पहुंचने दिया जाए या नहीं। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो नक्सली हमेशा से स्कूल और अस्पतालों पर हमला करते हैं और उनको नष्ट करने की फिराक में रहते हैं। उनका मानना है कि अगर सभी वर्गों तक सरकारी सुविधाओं या योजनाओं का लाभ पहुंच गया तो वर्ग संघर्ष के माध्यम से मजदूरों का राज कायम नहीं हो सकेगा। कम्युनिस्ट पार्टी में विभाजन के आधार को देखेंगे तो वहां भी भारत से अधिक रूस और चीन में व्याप्त विचारधारा का असर दिखता है। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी में जब विभाजन हुआ और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी बनी तो वैचारिक भिन्नता का आधार रूस और चीन की साम्यवादी विचारधारा थी। एक गुट रूस तो दूसरा चीन की विचारधारा को लेकर आगे बढ़ना चाहता था। जब देश आजाद हुआ था तो जवाहरलाल नेहरू रूस के अधिक करीब थे। रूस की कम्युनिस्ट पार्टी चाहती थी कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी नेहरू को लेकर उदार रहे। जबकि सीपीआई का एक गुट इसके खिलाफ था। 1962 में चीन के साथ युद्ध होने के बाद भी सीपीआई का एक गुट चीन की पैरोकारी में लगा रहा। माओ को लेकर नारा भी लगता था उनका चेयरमैन हमारा चेयरमैन। चीन के साथ युद्ध के दो वर्ष बाद पार्टी में विभाजन हुआ। जब राष्ट्र के निषेध की बात होती है तो कम्युनिस्टों की पुरानी वैचारिकी जीवंत हो उठती है।

केंद्र ने देश के आर्थिक भविष्य पर दिया ध्यान

सरकार ने चुनावी राजनीतिक हितों के आगे अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के दूरगामी लक्ष्य पर न केवल ध्यान केंद्रित किया बल्कि यह भी रेखांकित किया कि उसका उद्देश्य 2047 तक भारत को एक समर्थ-सक्षम देश के रूप में सामने लाना है। कोरोना संकट के बीच आया एक और आम बजट इसलिए विशेष रूप से उल्लेखनीय है, क्योंकि मोदी सरकार ने देश के आर्थिक भविष्य को सुधारने पर ध्यान दिया, न कि लोकलुभावन योजनाओं के जरिये फौरी वाहवाही पाने अथवा कोई राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश की। यह कदम एक ऐसे समय उठाया गया जब राजनीतिक दृष्टि से सबसे अहम राज्य उत्तर प्रदेश समेत पांच राज्यों के चुनाव होने जा रहे हैं और उन्हें लघु आम चुनाव की भी संज्ञा दी जा रही है। यह न केवल सरकार के आत्मविश्वास को प्रकट करता है, बल्कि यह भी इंगित करता है कि उसे यह भरोसा है कि देश की जनता उसकी ओर से उठाए जाने वाले कदमों का अनुमोदन करेगी। निःसंदेह अर्थनीति राजनीति से विरत नहीं हो सकती, लेकिन उसे इसका बंधक भी नहीं बनना चाहिए। यह सही है कि बजट में मध्य वर्ग को कोई वैसी राहत नहीं मिली जिसकी अपेक्षा की जा रही थी, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि सरकार ने पूंजीगत व्यय में भारी-भरकम व्यय करने की योजना बनाई उसके साकार होने से अंततः आम आदमी को ही लाभ मिलेगा। इसके साथ-साथ अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी। अर्थव्यवस्था को गति देने का काम शहरीकरण की उन योजनाओं को आगे बढ़ाने से भी होगा जिनका विवरण बजट में दिया गया है। शहरीकरण को प्राथमिकता देना समय की मांग है और जरूरत भी, क्योंकि आगामी कुछ वर्षों में देश की करीब पचास प्रतिशत आबादी शहरी क्षेत्रों में निवास करेगी। हमारे शहर न केवल आबादी के बढ़ते बोझ का वहन करने की क्षमता से लैस होने चाहिए, बल्कि उनमें विश्वस्तरीय सुविधाएं भी होनी चाहिए। जैसे जितना जरूरी यह था कि शहरों को संवारने पर ध्यान दिया जाए वैसे ही यह भी कि गांवों को और अधिक उन्नत एवं सुविधासंपन्न बनाया जाए। बजट रोजगार सृजन की संभावनाओं को भी जगा रहा है। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि ये संभावनाएं जगी रहें। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने न्यूनतम समर्थन मूल्य अर्थात एमएसपी जारी रहने का उल्लेख करते हुए जिस तरह यह रेखांकित किया कि इस मद में 2.37 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है वह यही बताता है कि सरकार ने उस दुष्प्रचार की हवा निकालना आवश्यक समझा जिसके तहत कुछ कथित किसान नेताओं के साथ कई विपक्षी नेता यह झूठ फैलाने में लगे हैं कि यह सरकार एमएसपी खत्म करने का इरादा रखती है।

गणतंत्र दिवस की क्षेत्रवासियों को
हार्दिक शुभकामनाएं
मा. तारा सिंह गुर्जर
सरपंच
श्री रामनरेश ठाकुर
सचिव
मा. भूपेन्द्र दुबे
रोजगार सहायक
सौजन्य- ग्राम पंचायत महूना गुर्जर राहतगढ़

समस्त पाठकों एवं विज्ञापनदाताओं को
गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई
विज्ञापन, समाचार एवं अखबार की प्रति प्राप्त करने के लिए
संपर्क करें
भगवान सिंह प्रजापति, संवाददाता स्वदेश ज्योति, राहतगण मो.- 9826948827

गणतंत्र दिवस
की सभी कृषकों एवं क्षेत्रवासियों को
हार्दिक शुभकामनाएं
मड़िया बांध बीना परियोजना
सौजन्य- एल.सी.सी. प्रोजेक्ट प्रा.लि.
अहमदाबाद गुजरात

गणतंत्र दिवस की क्षेत्रवासियों को
हार्दिक शुभकामनाएं
मा. गोविंद सिंह राजपूत
राजस्व एवं परिवहन मंत्री
मा. महेन्द्र सिंह सिसोदिया
पंचायत मंत्री
मा. गुलाब सिंह राजपूत
मंत्री प्रतिनिधि
मा. राजकुमार सिंह धनौरा
सरपंच संघ अध्यक्ष
श्रीमति क्रांतिबाई
जनपद अध्यक्ष
मा. एस.के. प्रजापति
सीईओ
मा. के.के. श्रीवास्तव
लेखा अधिकारी
सौ.- जनपद पंचायत कार्यालय राहतगढ़

गणतंत्र दिवस की क्षेत्रवासियों को
हार्दिक शुभकामनाएं
मा. रूप सिंह आठिया
सरपंच
मा. योगेश यादव
सचिव
मा. रमाकांत पचौरी
प्रभारी सचिव
सौ.:- ग्राम पंचायत उमरिया सेमरा राहतगढ़

गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं
मा. सुनील श्रीवास्तव
सरपंच
श्री कृष्णकांत देवलिया
सचिव
श्री रामकुमार गौर
रोजगार सहायक
सौजन्य- ग्राम पंचायत परासरी त्योंदा राहतगढ़

गणतंत्र दिवस की क्षेत्रवासियों को
हार्दिक शुभकामनाएं
मा. नसीम खान
वरिष्ठ समाज सेवी
मा. वसीम खान
जिला महामंत्री युवा कांग्रेस
मा. राणा खान
युवा उद्योगपति
सौजन्य- खान स्टोन क्रेशर मड़ला हिनौतिया

गणतंत्र दिवस की
हार्दिक शुभकामनाएं
मा. सुरेन्द्र रघुवंशी
युवा नेता
मा. रामदास मेहतर
सरपंच
मा. हरि सिंह यादव
सचिव
मा. नेतराम साहू
रोजगार सहायक
समस्त पंचगण व ग्रामवासी
सौजन्य- ग्राम पंचायत रजवांस राहतगढ़

गणतंत्र दिवस
की
हार्दिक शुभकामनाएं
अपील
वन एवं वन्यप्राणी देश की धरोहर है
इनके संरक्षण में सहयोग करें।
वनों की कटाई रोकने में
वन विभाग का सहयोग करें।
मा. सर्वेश सोनी
वन परिक्षेत्र अधिकारी
सौजन्य- वन परिक्षेत्र कार्यालय राहतगढ़

मा. गोविंद सिंह राजपूत
राजस्व व परिवहन मंत्री
मा. हरिनारायण गंधर्व
सरपंच
मा. योगेश यादव
सचिव
गणतंत्र दिवस
की
हार्दिक
शुभकामनाएं
मा. नवीन साहू
रोजगार सहायक
सौजन्य- ग्राम पंचायत गंभीरिया हाट राहतगढ़

गणतंत्र दिवस
की क्षेत्रवासियों को
हार्दिक शुभकामनाएं
मा. एस.के. प्रजापति, सीईओ मा. सुरेन्द्र सिंह दांगी, एसडीओ
सौजन्य- एसडीओ जनपद राहतगढ़

गणतंत्र दिवस की सभी नगरवासियों को
हार्दिक
शुभकामनाएं
मा. हेमराज कोरी
लेखापाल एवं
समस्त स्टाफ
मा. देवेन्द्र प्रताप सिंह
प्रशासक
मा. आर.सी. अहिरवार
सीएमओ
अपील- समस्त नगरवासी स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 को सफल बनाएं।
नगर परिषद के समस्त कर समय पर जमा करें।
सोशल डिस्टेंशन का पालन करें। हमेशा मास्क लगाएं।
सौ.- नगर परिषद कार्यालय राहतगढ़

गणतंत्र दिवस
की क्षेत्रवासियों को
हार्दिक शुभकामनाएं
श्रीमती चैनीबाई राजपूत
सरपंच
मा. सीताराम राजपूत
सरपंच प्रतिनिधि
मा. नंदराम राय
सचिव
मा. भानु सिंह राजपूत
रोजगार सहायक
सौ.:- ग्राम पंचायत झिला, राहतगढ़

गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं
मा. मन्नूलाल कबीरपंथी
सरपंच
मा. प्रेमनारायण किरार
सचिव
श्रीमती कृष्णा बाई, ग्राम रोजगार सहायक
सौ.:- ग्राम पंचायत हिरनखेड़ा, राहतगढ़

कम सिंचाई में किसानों को मिलेगा ज्यादा मुनाफा

जबलपुर कृषि विवि ने विकसित की गेहूं-धान-रामतिल-जई की किस्में

नई किस्में बढ़ाएंगी पैदावार

जबलपुर। संवाददता

मध्यप्रदेश की जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर ने गेहूं, धान, रामतिल, जई की 8 किस्मों को विकसित किया है। ये किस्में रोग प्रतिरोधी हैं और कम सिंचित वाले क्षेत्रों में भी आसानी से इनकी फसल हो सकेगी। 120 से 125 दिनों में ये फसलें होंगी। विवि की इन 8 नई किस्मों को भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने भी अधिसूचित कर दिया है। अब इसे ब्रीडर योजना के तहत बीज उत्पादन वाली इकाइयों को दिया जाएगा। विवि के डायरेक्टर, अनुसंधान सेवाएं जीके कौतू के अनुसार कृषि वैज्ञानिकों ने अनाज की आठ नई किस्में विकसित की हैं। इनमें से दो किस्में अधिक न्यूट्रीशन वाली हैं। जबकि 4 किस्में सिर्फ मप्र को ध्यान में रखकर विकसित की गई हैं। आदिवासियों के लिए लाभ की फसल माने जाने वाली रामतिल की तीन किस्मों को विकसित किया गया है। एक नेशनल किस्म है, तो दो किस्में मप्र और छत्तीसगढ़ को ध्यान में रखकर विकसित की गई हैं।

जौ10-506: उड़ीसा, बिहार, झारखंड, पूर्वी यूपी, असम, मणिपुर राज्यों के लिए उपयुक्त है। हरा चारा और बीजों के लिए इसकी बोवनी कर सकेंगे। 90 से 100 दिन हरा चारा के रूप में प्रयोग करें। 225 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हरा चारा का उत्पादन होगा। एक कटिंग के बाद छोड़ दें। 10 से 11 क्विंटल प्रति हेक्टेयर जई भी तैयार हो जाएगी। **जौ 05-304:** मप्र, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, बुंदेलखंड राज्यों के लिए ये मुफीद होगा। इसकी कटिंग भी 90 से 100 दिन में कर सकते हैं। पहली कटिंग 55 से 60 दिन में कर पाएंगे। हरा चारा प्रति हेक्टेयर 560 से 600 क्विंटल प्राप्त कर सकते हैं। इसे खिलाने से पशु दुग्ध उत्पादन और फैट दोनों बढ़कर मिलेगा।

रामतिल की तीन किस्में

जोएनएस-521: असिंचित और सिंचित दोनों क्षेत्रों में खरीफ और रबी में इसकी बोवनी कर सकेंगे। ये शीघ्र पक जाएंगी। 100 से 110 दिन में ये पक कर काटने लायक हो जाएगी। 5 से 6 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसका उत्पादन होता है। ये आदिवासी बेल्ट में बोया जाता है। वहां घी के विकल्प के तौर पर इसका प्रयोग करते हैं। 80 रुपए प्रति किलो की दर से इसकी बिक्री होती है।

जेनएस-2015-9: मप्र और छत्तीसगढ़ को ध्यान में रखकर ये किस्में विकसित की गई हैं। सिंचित और असिंचित क्षेत्र में मध्य खरीफ के समय इसकी बोवनी करें। 100 दिन में ये तैयार हो जाएगी। इससे जेएनएस-9 की तुलना में 10 प्रतिशत अधिक उपज और 9 प्रतिशत अधिक तेल की मात्रा मिलेगी। पौधे छोटे होंगे और गिरेंगे नहीं। कई गंभीर बीमारी और कीटों से प्रतिरोधी किस्म है। 541 किलो प्रति हेक्टेयर उत्पादन होगा।

जेएनएस-2016-1115: इसे देश के किसी भी हिस्से में बो सकेंगे। सिंचित और असिंचित दोनों क्षेत्रों में इसकी बोवनी हो सकेगी। मध्य खरीफ में इसकी बोवनी कर सकेंगे। इससे अधिक उपज प्राप्त होगी। रामतिल के साथ किसान मधुमक्खी पालन भी कर पाएंगे। इससे एक से दो क्विंटल जहां उत्पादन बढ़ जाएगा। वहीं तीन से चार हजार रुपए प्रति एकड़ प्राप्त राशि भी प्राप्त कर पाएंगे।

गेहूं की दो किस्मों का किया विकास

मप्र-1323: पूरे प्रदेश में इसकी बोवनी हो सकेगी। उत्तम उपज, रोग प्रतिरोधक, अधिक प्रोटीन होगा। औसत पैदावार 55 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होगी। 125 दिन में ये तैयार हो जाएगा।

मप्र-1358: अधिक उपज प्राप्त होगी। औसत पैदावार 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होगी। इसमें प्रोटीन 12 प्रतिशत से अधिक होगा। आयरन की मात्रा 406 पीपीएम होगी। गेहूं की ये फसल भी 125 से 130 दिन में तैयार हो जाएगी।

धान की एक किस्म

जेआर-10: कम सिंचाई में अधिक उपज किसान प्राप्त कर सकेंगे। पूरे एमपी में इसकी रोपाई कर सकेंगे। इसके चावल पतले और सुगंधित होंगे। 55 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन होगा। 120 दिन में ये धान तैयार हो जाएगा।

किसानों को अभी इंतजार

किसानों को इन नई किस्मों के लिए अभी एक साल और इंतजार करना होगा। इस साल अभी ब्रीडर बीज के तौर पर इसका उत्पादन कराएंगे। इसके बाद ये सर्टिफाइड बीज के तौर पर किसानों को 2024 से उपलब्ध होगी। आठ नई किस्में किसानों के लिए किसी क्रांति से कम नहीं होंगी। ये सभी किस्में बदलते जलवायु परिवर्तन के प्रति सहनशील होंगी।

तीन दिवसीय प्रशिक्षण में पढ़ाया पाठ

आय का अच्छा स्रोत कड़कनाथ मुर्गीपालन, किसान आएं आगे

विनोद पांडेय, दतिया।

कृषि विज्ञान केंद्र दतिया पर तीन दिवसीय कड़कनाथ मुर्गीपालन विषय पर प्रशिक्षण केंद्र के प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. आरकेएस तोमर के मार्ग दर्शन एवं प्रशिक्षण समन्वय डॉ. रूपेश जैन के तकनीकी निर्देशन में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के उद्घाटन अवसर पर केंद्र के प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को खेती के साथ छोटे स्तर पर कड़कनाथ मुर्गीपालन करने की सलाह दी गई। कार्यक्रम के शुभारंभ में मुख्य अतिथि डॉ. आरएस यादव, निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान संस्थान दतिया द्वारा कृषकों को कड़कनाथ मुर्गीपालन के लिए प्रेरित किया गया। विषय विशेषज्ञ डॉ. रूपेश जैन द्वारा तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की विस्तृत कार्ययोजना प्रशिक्षणार्थियों को समझाई गई। प्रशिक्षण के तकनीकी सत्र में डॉ. जैन द्वारा किसानों को बताया गया कि कड़कनाथ मुख्यत: मप्र के धार और झाबुआ में पाई जाने वाली कुक्कुट की नस्ल है। इसका रंग पूर्ण रूप से काला होता है। बाजार में इसका दाम अन्य नस्लों की अपेक्षा कहीं ज्यादा होता है। इसमें उच्च स्तरीय पोषक तत्व पाये जाते हैं। इनमें प्रोटीन की मात्रा अन्य प्रजाति की तुलना में सबसे ज्यादा होती है। साथ ही वसा (कोलेस्ट्राल) की मात्रा सबसे कम होती है। इस कारण इसकी बाजार में मांग अन्य नस्लों की अपेक्षा कहीं ज्यादा होती है। साथ ही इनमें कई औषधीय गुण भी होते हैं, जिस वजह से किसान इन्हें पालना ज्यादा पसंद करते हैं। प्रशिक्षण के द्वितीय दिन डॉ. जैन द्वारा कड़कनाथ मुर्गी के आहार प्रबंधन एवं बीमारियों के प्रबंधन विषय पर विस्तार से जानकारी दी गई।

मुर्गियों को समय पर टीका लगवाना जरूरी

डॉ. जैन ने बताया कि रानीखेत एवं गम्बोरो बीमारी मुर्गियों की प्रमुख बीमारी है जिनसे बचाव के लिए मुर्गियों को समय-समय पर टीके लगवाना अति आवश्यक है। रानी खेत बीमारी का टीका 6वें दिन पर तथा गम्बोरो बीमारी का 14-15 दिन के चूजे पर लगाना चाहिए। डॉ. वीएस कंसाना ने अजोला उत्पादन की जानकारी प्रशिक्षणार्थियों को दी। तृतीय दिवस डॉ. जैन ने विभिन्न ऋतुओं में शीत, ग्रीष्म एवं वर्षा ऋतु में मुर्गियों को आवश्यकता अनुसार उचित प्रबंधन करना चाहिए। केन्द्र के वैज्ञानिक डॉ. नरेश गुप्ता द्वारा कड़कनाथ मुर्गी की आर्थिकी के बारे में किसानों को समझाइश दी गई। प्रशिक्षण में दतिया जिले के 40 मुर्गीपालक कृषकों ने भाग लिया। प्रशिक्षण में समस्त प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए।

दूध के साथ खाद और कीटनाशक बेचेंगे

गायों की देखरेख और गोबर गैस उत्पादन होगा

उज्जैन में अब ठेके पर देंगे कपिला गौशाला

उज्जैन। संवाददाता

नगर निगम की रत्नाखेड़ी स्थित कपिला गौशाला का संचालन अब निजी संस्था को दिया जाएगा ताकि गायों की देखभाल के साथ गौशाला से दूध, खाद, कीटनाशक और गोबर गैस का उत्पादन किया जा सके। इसे आदर्श गौशाला का स्वरूप भी दिया जाएगा। निगम ने शहर से पकड़े गए मवेशियों को रखने के लिए शहर से 14 किमी दूर ग्राम रत्नाखेड़ी में 2015 में गौशाला शुरू की थी। सात हेक्टेयर जमीन पर बनी गौशाला में चार शेड, कार्यालय भवन व भूसा घर का निर्माण किया था। यहां 1100 गायों को रखने की व्यवस्था है। मौजूदा स्थिति में यहां 700 गाय हैं। निगम ने इस गौशाला का राज्य शासन के पशु पालन बोर्ड में भी पंजीयन कराया है। गौशाला का संचालन निगम के कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। यह प्रशिक्षित नहीं है। इसलिए गौशाला का संचालन वैज्ञानिक विधि से नहीं हो रहा। निगमायुक्त अंशुल गुप्ता के अनुसार गौशाला को आदर्श स्वरूप देने के साथ यहां से दूध, जैविक खाद, कीटनाशक और गोबर गैस का उत्पादन कर गोशाला को आर्थिक रूप से समृद्ध करने के लिए निगम इसका संचालन इस काम में दक्ष संस्था या व्यक्ति को देगा। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इस पर नियंत्रण और निर्णय लेने के अधिकार निगम के पास ही रहेंगे।

संचालनकर्ता को मिलेंगे अधिकार

पशु पालन बोर्ड से आर्थिक मदद संचालनकर्ता को दी जाएगी। पकड़े मवेशियों के अलावा दूध के लिए अतिरिक्त मवेशी रख सकेंगे। गोबर से गैस और खाद की बिक्री से प्राप्त राशि संचालनकर्ता लेगा। गौमूत्र से बनने वाले कीटनाशक से होने वाली आय संचालनकर्ता की होगी।

यह करना होगा

कर्मचारी, डॉक्टर, इलाज, सफाई, चारा, पानी की व्यवस्था। दूध, गैस, खाद बनाने के लिए जरूरी कर्मचारी की व्यवस्था।

निगम को होगा फायदा

गौशाला में कर्मचारियों को तैनात नहीं करना पड़ेगा। यह कर्मचारी निगम के अन्य काम संभालेंगे। निगम को गोशाला संचालन पर खर्च नहीं करना पड़ेगा। इससे निगम को आर्थिक बचत होगी।

जैविक खेती कर अविनाश सिंह ने बनाई अपनी अलग पहचान

खरगोन के किसान ढाई एकड़ में 70 तरह की ले रहे फसलें

खरगोन। संवाददाता

देशभर में किसानों की रुचि जैविक खेती की तरफ बढ़ रही है। जिसके चलते अच्छी कमाई भी हो रही है। कई गांवों में जैविक खेती को लेकर किसानों को जागरूक करने की मुहिम भी चलाई जा रही है। लेकिन मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के बिस्टान गांव के रहने वाले अविनाश सिंह डांगी जिले में जैविक खेती के लिए प्रसिद्ध हैं। दरअसल, अविनाश सिंह डांगी अभिनेता जैकी श्रॉफ से मिलने मुंबई पहुंचे थे। तब अभिनेता ने किसान को समझाया कि, फसलें बच्चों की तरह होती हैं और अपने बच्चों को रासायनिक कीटनाशक नहीं खिलाना चाहिए। उस दिन से किसान के लिए अभिनेता प्रेरणास्त्रोत तो बन ही गए और शुरुआत हुई जैविक खेती की।

-शुरुआत में किया मुश्किलों का सामना

जैविक खेती शुरू करने से पहले अविनाश सिंह डांगी ने काफी जानकारियां ली और खुद कृषि वैज्ञानिकों से संपर्क किया। जैविक खेती की शुरुआत करते समय उन्हें काफी मुश्किलें आई और यह उनके लिए तब और मुश्किल हो गया जब गांव के लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि, खेती की परंपरा जो पहले से चली आ रही है, उसे एक अभिनेता के कहने पर कैसे बदला जा सकता है। लेकिन अविनाश ने किसी की नहीं सुनी और इसे से धीरे-धीरे जैविक खेती में नए आयाम स्थापित होते चले गए।

जबरदस्त अविनाश का मॉडल

आज अविनाश सिंह डांगी ने जैविक खेती का एक ऐसा मॉडल स्थापित किया है, जिसमें मात्र ढाई एकड़ में 70 तरह की विभिन्न फसलें ले रहे हैं। जैविक पद्धति से इस नए मॉडल की शुरुआत उन्होंने जून 2021 में की थी और यह जून 2022 तक चलेगी। जिसमें उन्होंने 18 तरह कि सब्जी, 32 तरह के फल, 4 तरह के मसाला फसलें लगाई है। 21 कतारों में अलग-अलग फसलें हैं। जून से दिसंबर तक हरा धनिया, मूंगफली, उड़द, गेंदा स्वीट कॉर्न की फसल है। उनके खेती के मॉडल में 32 तरह की विभिन्न फसलें लगी हुई है।

अलग-अलग फसलों की खेती

अविनाश सिंह डांगी अपनी खेती के लिए खाद और कीटनाशक देशी गाय के गोबर से खुद तैयार करते हैं, जिससे वह अपनी फसलों में प्राकृतिक खाद और कीटनाशक का इस्तेमाल कर सकें। वहीं, मल्टी लेयर, मल्टी क्रॉप, फ्रूट फॉरेस्ट, फैमिली फार्मिंग मॉडल तैयार किया है। जिसके तहत जमीन के अंदर से ऊपर तक 6 से 5 परतों में अलग-अलग फसलों की खेती होती है।

जैविक खेती में मुनाफा ज्यादा

आज भी जो किसान पुरानी परंपरा के मुताबिक ही खेती कर रहे हैं, उनकी लागत ज्यादा और मुनाफा कम की स्थिति रहती है। लेकिन जैविक खेती में मुनाफा काफी ज्यादा है। जिसको अपनाते हुए बाकि किसान भी इसका फायदा उठा सकते हैं। जिस तरह अभिनेता जैकी श्रॉफ किसान अविनाश के लिए प्रेरणा बने थे, उसी तरह से बाकी किसान भी अविनाश से प्रेरणा ले सकते हैं।

ड्रिप से कर रहे सिंचाई

अविनाश सिंह डांगी बताते हैं कि मल्टी लेयर, मल्टी क्रॉप, फ्रूट फॉरेस्ट, फैमिली फार्मिंग मॉडल तैयार किया है। जिसमें मल्टी लेयर का मतलब है कि भूमि के अंदर से ऊपर तक 6 से 5 परतों में विभिन्न फसलों की खेती होती है। ऐसे मॉडल में किसी भी परिवार की जरूरत के मुताबिक हर सीजन में हर फल सब्जी आना ज्यादा उपलब्ध होगी। इसी प्रबंधन के साथ हर एक फसल को लगाया गया है। इस मॉडल में वे ड्रिप से सिंचाई करते हैं।

रासायनिक खाद से दूरी

अविनाश बताते हैं कि वह अपने खेत में रासायनिक खाद एवं कीटनाशक का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करते। इसके लिए वह अपने खेत में ही जैविक पद्धति से वर्मी कंपोस्ट, घन जीवामृत, सत्पर्णी अर्क, एवं ऐसे जंगली पौधे जिन्हें मवेशी नहीं खाते उनके पत्तों से जैविक कीटनाशक तैयार कर अपनी फसलों पर छिड़काव करते हैं। दूसरे किसान जो पुराने ढर्रे से खेती करते चले आ रहे हैं उनको खेती में लागत अधिक एवं मुनाफा कम मिल रहा है लेकिन ऐसे किसान जी ने खेती में कुछ अलग करना हो तो वह अविनाश से प्रेरणा लेकर खेती के नए मॉडल की शुरुआत कर सकते हैं।

कृषि विज्ञान केंद्र में राष्ट्रीय बालिका दिवस का आयोजन

बेटियां हमारी धरोहर हैं, जिन्हें हम संरक्षित करना हमारा कर्तव्य

डिंडोरी। संवाददाता

जवाहरलाल नेहरू कृषि विज्ञान केंद्र के अंतर्गत संचालित इकाई कृषि विज्ञान केंद्र डिंडोरी महिला बाल विकास विभाग एवं नेहरू युवा केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रीय बालिका दिवस का आयोजन केंद्र के सभागार में आयोजित किया गया। उक्त कार्यक्रम के मार्गदर्शक पीएल अमूल वरिष्ठ वैज्ञानिक वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र डिंडोरी के मार्गदर्शन में कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ में मंजू लता सिंह जिला महिला बाल विकास अधिकारी के मार्गदर्शन में कृषि विज्ञान केंद्र डिंडोरी एवं नेहरू युवा केंद्र एवं खेल विभाग के संयुक्त तत्वाधान में कृषि विज्ञान केंद्र में बालिका दिवस का सम्मान समारोह किया गया। उक्त कार्यक्रम रेनू पाठक कार्यक्रम प्रभारी तकनीकी अधिकारी द्वारा राष्ट्रीय बालिका दिवस के ऊपर प्रकाश डालते हुए कहा कि बेटियां हमारी धरोहर हैं, जिन्हें हम संरक्षित करना हमारा कर्तव्य है हमें बेटियों पर गर्व होनी चाहिए। बेटी है तो कल है का नारा देते हुए रेनू पाठक ने आह्वान किया कि बेटी हमारे देश के भविष्य हैं जिन्हें हमारा कर्तव्य है कि आगे बढ़ाने का संकल्प लेना चाहिए। उक्त कार्यक्रम में श्याम सिंह गौर सहायक संचालक महिला बाल विकास विभाग डिंडोरी द्वारा बालिकाओं को आगे आने की बात कही और कहा कि बेटियां हमारे गर्व है देश के भविष्य में बहुत बड़ा योगदान है।

राष्ट्रीय बालिका दिवस का आयोजन

पन्ना। कृषि विज्ञान केन्द्र पन्ना द्वारा ग्राम तिलगुवां में राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में डॉ. आरके जायसवाल द्वारा उपस्थित बालिकाओं को बालिका शिक्षा एवं उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के लिए संदेश दिया साथ ही सभी बालिकाओं को फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। बालिकाओं को पोषण आहार के बारे में विस्तार से बताया गया। उन्हें बताया गया कि अपने दैनिक भोजन आहार में विशेष रूप से हरी सब्जियों का सेवन करने की सलाह दी गई, जिससे बालिकाओं में लोहतत्व की कमी को दूर किया जा सके। कार्यक्रम में उपस्थित बालिकाओं के पालकों को उनकी शिक्षा एवं स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने की सलाह दी गई साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश भी दिया गया। कार्यक्रम में केन्द्र के डॉ. आरपी सिंह, रितेश बागोरा सहित पंचायत सचिव सहित 45 बालिकाओं ने भाग लिया।

गौर गांव में राष्ट्रीय बालिका दिवस का आयोजन

टीकमगढ़। कृषि विज्ञान केंद्र टीकमगढ़ एवं मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन के संयुक्त तत्वाधान में ग्राम गौर विकासखंड बल्देवगढ़ में राष्ट्रीय बालिका दिवस का आयोजन किया गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2008 में राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष मनाना प्रारंभ किया गया है, जिसका उद्देश्य बालिकाओं मैं शिक्षा स्वास्थ्य एवं पोषण के लिए जागरूक करना है। कार्यक्रम में प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. बीएस किरार डॉ. आरके प्रजापति डॉ. एसके सिंह डॉ. यूएस धाकड़ वैज्ञानिक एवं मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन से मोहम्मद आयूब कुरैशी, रूपेंद्र सिंह एवं राहुल मिश्रा आदि द्वारा भाग लिया गया। डॉ. किरार ने बालिका दिवस कार्यक्रम में कहा कि ग्रामीण एवं शहरी दोनों की बालिकाओं के समुचित विकास के लिए शिक्षा ग्रहण करना अति आवश्यक है। शिक्षा से रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे साथ ही एक आदर्श परिवार का निर्माण करेंगे।

बजट में किया जाएगा विशेष प्रविधान, कृषि उद्यमों को मिलेगा प्रोत्साहन

हरितक्रांति की तर्ज पर अब होगी एवरग्रीन क्रांति

भोपाल/नई दिल्ली। संवाददता

देश को खाद्य सुरक्षा के साथ पोषण सुरक्षा प्रदान करने के लिए आगामी वित्त वर्ष 2022-23 के आम बजट में विशेष प्रविधान किया जाएगा। खाद्यान्न उत्पादन के मामले में आत्मनिभ्ज़रता के लिए हरितक्रांति का नारा दिया गया, उसी तर्ज पर आगामी बजट में एवरग्रीन क्रांति के नारे दिए जा सकते हैं। सरकार की चिंता देश में कुपोषण की समस्या को लेकर है। इसे गंभीर चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने बजट प्रस्तावों में इसे प्राथमिकता दे सकती हैं। देश की बड़ी आबादी को पर्याप्त मात्रा में अनाज भले ही मिल जाता हो, लेकिन उसमें जरूरी पौष्टिकता का अभाव उसके पोषण में असंतुलन पैदा करता है। खाद्यान की आयात निर्भरता खत्म करने के लिए देश में वर्ष 1960 और 70 के दशक में हरितक्रांति का नारा दिया गया, जिससे अगले एक दशक के भीतर ही भारत गेहूं और चावल की भारी पैदावार से पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो गया।

देश कई जिंसों का निर्यातक

यही नहीं, देश में दूसरी हरितक्रांति का नारा दिया गया था, जिसका नतीजा यह रहा कि देश कई जिंसों का निर्यातक बन गया। देश में फिलहाल सिर्फ खाद्यान्न की पैदावार 30 करोड़ टन से अधिक होने लगी है, जो घरेलू खपत से बहुत अधिक है। सरप्लस पैदावार की वजह से ही कोरोना के इस विकट समय में भी देश की दो तिहाई आबादी को पिछले डेढ़ दो सालों से मुफ्त अनाज वितरित किया जा रहा है।

कुपोषण की समस्या

हरितक्रांति के बाद कृषि क्षेत्र में हुआ असंतुलित विकास गंभीर चुनौतियां लेकर सामने खड़ा है। भोजन में शामिल तीन प्रमुख तत्वों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट में से धीरे-धीरे दो तत्व छूमंतर हो गए। भोजन की ताली में कार्बोहाइड्रेट (अनाज) तो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है , लेकिन अन्य जरूरी तत्वों फैट और प्रोटीन की कमी से कुपोषण की समस्या हो रही है।

बिगड़ा थाली का संतुलन

देश वैश्विक हंगर इंडेक्स की सूची में निचले पायदान पर है, लेकिन सरकार थाली के बिगड़े इस असंतुलन को लेकर सतर्क है, जिसे ठीक करना उसकी प्राथमिकता में शामिल है। एवरग्रीन क्रांति के तहत सरकार कृषि क्षेत्र में खेती के असंतुलन को दुरुस्त करेगी। उन सभी फसलों की खेती पर जोर दिया जाएगा, जिससे खाद्य तेल और प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा गरीब से गरीब व्यक्ति को आसानी से उपलब्ध हो सके।

दलहन फसलों पर फोकस

इसी के तहत तिलहन व दलहन फसलों की खेती को प्रोत्साहित किया जाएगा। डेयरी उत्पादों की उपलब्धता बढ़ाई जाएगी। पोल्ट्री और मछली पालन को विशेष तरजीह दी जाएगी ताकि लोगों को भोजन में कार्बोहाइड्रेट के साथ जरूरी प्रोटीन और फैट की मात्रा को बढ़ाया जा सके। हालांकि, इसी के तहत पहले चरण में स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषक तत्व मिश्रित चावल की आपूर्ति की जा रही है।

डेयरी का देंगे प्रोत्साहन| दूसरे चरण में अगले दो तीन वर्षों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सभी राशनकार्ड वाले उपभोक्ताओं को पोषक तत्व मिश्रित अनाज ही दिया जाएगा, लेकिन इस स्थिति से निपटने के स्थायी उपाय को एवरग्रीन क्रांति का नाम दिया जाएगा, इसमें उन फसलों और उत्पादों पर जोर दिया जाएगा, जिनसे गरीबों की थाली तंदुरुस्त होगी। इसके साथ ही बागवानी, पोल्ट्री, मत्स्य और डेयरी को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। परंपरागत फसलों में उन पर ज्यादा बल दिया जाएगा, जो पौष्टिकता से भरपूर हैं।

आज़ादी का अमृत महोत्सव
मध्यप्रदेश शासन

देश के लिए बलिदान होने वाले वीर सपूतों को शत्-शत् नमन।

श्री नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री

श्री शिवराज सिंह चौहान
मुख्यमंत्री

73 वें गणतंत्र दिवस की प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएँ

शिवराज सिंह चौहान
मुख्यमंत्री

जनभागीदारी से आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश जनसम्पर्क द्वारा जारी
D-18222/21
आकल्पन : मध्यप्रदेश माध्यम/2022

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादक: अजय कुमार द्विवेदी, स्थानीय संपादक- **अरविंद मिश्र, संपर्क** -9229497393, 9425048589, ईमेल:- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)